



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2512]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 5, 2018/आषाढ़ 14, 1940

No. 2512]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 5, 2018/ASHADHA 14, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2018

का. आ.3266(अ). – आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के निवारण और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और आर्मेनिया गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय जिस पर 31 अक्टूबर, 2003 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध में उपवर्णित के अनुसार उस पर 27 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए हैं जैसा कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध उपाबंध में दिया गया है और जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त संशोधनकारी प्रोटोकाल कहा गया है।

और उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख 14 जून 2017 है यह तारीख उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 2 के पैरा 1 के अनुसार उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल को प्रभावी करने के लिए विधिक अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए पश्चातवर्ती अधिसूचनाओं की तारीख है;

और उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 2 का पैरा 2 उपबंध करता है कि उसके उपबंध उसके प्रवृत्त होने की तारीख से तुरंत प्रभावी हो जाएंगे;

अतः केंद्रीय सरकार अब आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करती है कि उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के सभी उपबंध 14 जून 2017, वह तारीख जिसको उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल प्रवृत्त हुआ था, भारत संघ में प्रभावी होंगे।

(अधिसूचना सं. 30/फा.सं. 503/05/1996-एफटीडी-I)]

प्रजा एस.सक्सेना, संयुक्त सचिव

उपाबंध**प्रोटोकोल**

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्त अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और आर्मेनिया गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय जिस पर 31 अक्टूबर, 2003 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। को संशोधित करता है,

भारत गणराज्य की सरकार

और

आर्मेनिया गणराज्य की सरकार

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और आर्मेनिया गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय, जिस पर 31 अक्टूबर, 2003 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे और जो 9 सितम्बर, 2004 (जिसका इसके बाद “अभिसमय” के रूप में उल्लेख किया गया है) को लागू किया गया था, को संशोधित करने के लिए एक प्रोटोकोल (जिसका इसके बाद “प्रोटोकोल” के रूप में उल्लेख किया गया है) निष्पन्न करने की इच्छा से,

निम्नानुसार सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद 1

अभिसमय के अनुच्छेद 26 (सूचना का आदान-प्रदान) के पाठ को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“अनुच्छेद 26**सूचना का आदान-प्रदान**

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों को लागू करने के लिए अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन के लिए आवश्यक हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. पैराग्राफ 1 के अंतर्गत संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई किसी सूचना को उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना के समान ही गुप्त समझा जाएगा और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों का निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। पूर्ववर्ती पैराग्राफों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना को दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है जब ऐसी सूचना को दोनों राज्यों के कानूनों के अंतर्गत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाए और आपूर्तिकर्ता संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को अधिकृत करे।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ;

(ख) ऐसी सूचना की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

(ग) ऐसी सूचना की आपूर्ति करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक)।

4. इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई सूचना को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने की अनुमति नहीं होगी क्योंकि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने की अनुमति नहीं होगी कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नाभिमती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।”

अनुच्छेद 2

1. संविदाकारी राजनयिक माध्यमों से एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे कि इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए सभी कानूनी अपेक्षाओं एवं प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है।

2. प्रोटोकॉल, जो अभिसमय के अभिन्न अंग के रूप में होगा, पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होगा और इसके उपबंध तुरन्त लागू होंगे।

जिसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरी, जिन्हें उनकी सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत किया गया है, ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार सोलह के जनवरी माह के 27 दिन हिन्दी, आर्मेनियन एवं अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

अरूण कुमार जैन, अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड

आर्मेनिया गणराज्य की सरकार की ओर से

आर्मेन मार्टिरोशियान,

भारत गणराज्य में आर्मेनिया गणराज्य के
राजदूत असाधारण तथा पूर्णाधिकारी

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2018

S.O. 3266(E).— Whereas, the Protocol, amending the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Armenia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income which was signed at New Delhi on the 31st October, 2003, has been signed at New Delhi on the 27th January, 2016, as set out in the annexure appended to this notification and hereinafter referred to as the said amending Protocol;

And whereas, the date of entry into force of the said amending Protocol is the 14th June, 2017 being the date of the later of the notifications of completion of the legal requirements and procedures for giving effect to the said amending Protocol in accordance with paragraph 1 of Article 2 of the said amending Protocol;

And whereas, paragraph 2 of Article 2 of the said amending Protocol provides that the provisions of the same shall have effect forthwith from the date on which it enters into force;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the said amending Protocol, shall have effect in the Union of India with effect from the 14th day of June, 2017, being the date on which the said amending Protocol entered into force.

[Notification No. 30/F.No. 503/05/1996-FTD-I]

Pragya S. Saksena, Jt. Secy.

ANNEXURE

PROTOCOL

AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, WHICH WAS SIGNED AT NEW DELHI ON 31ST OCTOBER 2003.

The Government of the Republic of India

And

the Government of the Republic of Armenia;

Desiring to conclude a Protocol (hereinafter referred to as “Protocol”) to amend the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Armenia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, which was signed at New Delhi on 31st October, 2003 and which entered into force on 9th September, 2004 (hereinafter referred to as “the Convention”);

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

The text of Article 26 (Exchange of Information) of the Convention shall be replaced by the following:

“Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of , the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both Contracting States and the competent authority of the supplying Contracting State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other Contracting State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

ARTICLE 2

1. The Contracting States shall notify each other through diplomatic channels that all legal requirements and procedures for giving effect to this Amending Protocol have been satisfied.

2. The Protocol, which shall form an integral part of the Convention, shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect forthwith.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done in duplicate at New Delhi on this 27th day of January, 2016, each in Hindi, Armenian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of India

Arun Kumar Jain, Chairman,
Central Board of Direct Taxes

For the Government of the Republic of Armenia

Armen Martirosyan, Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of the Republic of Armenia to
the Republic of India